

विचार बिन्दु

कदम पीछे ना हटाने वाला ही ऐश्वर्य को जीतता है। –ऋग्वेद

जीवनशैली को बदल रही आर्थिक नीतियां और प्रौद्योगिकी

खुली आर्थिक नीतियों के बाद दो दशकों में भारत की सामाजिक संरचना में भले ही ज्यादा बदलाव नहीं हुआ हो, किन्तु डिजिटल तथा अन्य तकनीकी विकास के कारण यहां के लोगों की आदतों और रीति-रिवाजों में व्यापक परिवर्तन जरूर नज़र आता है। यह परिवर्तन केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, आपसी संबंध, काम करने के तरीकों और उपभोग की संस्कृति तक फैले हुए हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ई-कॉमर्स ने भारतीय उपभोक्ता को रात और दिन चौबीसों घंटे बाज़र से जोड़ दिया है। अब खरीदारी केवल ज़रूरत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इच्छा-आधारित उपभोग का रूप ले चुकी है। ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लैश सेल और डिजिटल भुगतान ने खर्च को सहज बनाया है।अभी खरीदो, बाद में चुकाओ जैसी सुविधाओं ने ऋण-आधारित जीवनशैली को बढ़ावा दिया है। डिजिटल तकनीक रोजगार और कार्य-संस्कृति को भी नया रूप दे रही है। वर्क फ्रॉम होम, प्रीलांसिंग और गिग इकॉनॉमी समय और स्थान की बाधा तोड़ रही है। सोशल मीडिया और मेसेजिंग ऐपस ने संवाद को तेज़ और व्यापक बना दिया है, पर ऐसा भी माना जाता है कि उसकी गहराई कम कर दी है। यह भी लग रहा है कि परिवार और पड़ोस के आपसी प्रत्यक्ष संवाद में कमी आ रही है। स्टार्ट-अप संस्कृति और ऐप-आधारित सेवाओं ने युवाओं में उछमिता की सोच को बढ़ावा दिया है। नौकरी की स्थिरता घटी है और कार्य तथा निजी जीवन की सीमाएं धुंधली होने लगी हैं। तकनीक ने जीवन को तेज़, प्रतिस्पर्धी और परिणाम-केंद्रित बना दिया है। धैर्य, प्रतीक्षा और संतोष जैसी प्रवृत्तियां कमजोर हुई हैं। सब कुछ तुरंत चाहिए वाली मानसिकता विकसित हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समय और जीवन के संतुलन पर पड़ रहा है। लोगों की जीवनशैली तो स्पष्ट रूप से बदल रही है। छोटी जगहों के युवा अच्छे पैकेज पर अपनी जगह छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। ऊंची-ऊंची फ्लैटों वाली बिल्डिंगें हमारे शहरों की पहचान बदल रही हैं। आधिकारिक तौर पर सबसे अधिक शुद्धतावादी माने वाले भारतीय समाजमें यौन अनुमति देने वाली पीढ़ी विस्तार पा रही है। शहरी जीवन का नया बहुराष्ट्रीय और बहुजातीय चरित्रबन रहा है। नये समय में एक तरफ जहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ गांवों में अब भी झोपड़ियों में जीवन बिताते लोग भी मिलते हैं और शहरों में कच्ची बस्तियों का जाल हर कहीं नज़र आता है। खुली अर्थनीतियों और नये नैतिक प्रतिमानों में लोग राजशाही के नॉस्टैल्लिया, वंशानुगत वंशवली, शासकीय सम्मान और आर्डरपूर्ण रीति-रिवाजों और समारोहों के बोझ से दबे हुए नज़र आते हैं। देश में संवैधानिक-गणतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद अनेक मौकों पर यहां की शासन व्यवस्था राजसी टसक वाली और वैसी ही अन्यायपूर्ण भी देखने को मिलती है।

भारत मिथकों से प्यार करने वाला देश रहा है। इसी कारण यहां की सामाजिक स्थिति का यथार्थवादी मूल्यांकन करना हमेशा ही कठिन रहा है। अंग्रेजों के जागे के बाद हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया मगर ब्रिटेन के 1935 के कानून की मूलभूत संरचनाओं में वास्तविक और बड़ा जमीनी परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। समग्र रूप से देखें तो पाते हैं कि इस कारण देश में आजादी के बाद वर्ग संरचना या व्यवसायों के वितरण तथा प्रशासन में कोई क्रांतिकारी या नाटकीय परिवर्तन नहीं हो पाया है। भले ही कृषि की जीडीपी में भूमिका कम होकर करीब 14 प्रतिशत रह गई है, मगर उस पर अब भी 45 प्रतिशत आबादी आश्रित है। राज्य अब भी प्रमुखता वाला और लोकप्रिय नियोजन बना हुआ है। अधिकतर श्रमिक अकुशल हैं, और वे रोज़ गांवों से चल कर नजदीकी शहरों में मजदूरी के लिए आते हैं। अतीत के श्रमिक वर्ग समुदाय, एकजुटता वाले संगठन अपना जुझारू चरित्र खो चुके हैं। भारत में वर्ग मतभेद न केवल मजबूत बने हुए हैं बल्कि अब तो वे अहंकारी में बदल गए हैं। साधन संपन्न लोगों के सभी चुनिंदा निजी शिक्षण संस्थान व्यावसायिक हो गये हैं जिनकी फ़ीसें चौकने वाली हैं। ऐसी पब्लिक स्कूलें अप्रतिम समृद्धि अर्जित करती हैं। शिक्षा आगे बढ़ने की सीढ़ी बनने के बजाय एक ऐसी छलांग बन गई है, जो गरीब नहीं लगा पाता। यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है जो अब पूरी तरह कॉर्पोरेट जगत के अधीन हो चुकी हैं और

तकनीक ने जीवन को तेज़, प्रतिस्पर्धी और परिणाम-केंद्रित बना दिया है। धैर्य, प्रतीक्षा और संतोष जैसी प्रवृत्तियां कमजोर हुई हैं। सब कुछ तुरंत चाहिए वाली मानसिकता विकसित हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक समय और जीवन के संतुलन पर पड़ रहा है। लोगों की जीवनशैली तो स्पष्ट रूप से बदल रही है। छोटी जगहों के युवा अच्छे पैकेज पर अपनी जगह छोड़ कर बाहर जा रहे हैं।

खुली है, केवल उनके बाहरी होने की भावना को रेखांकित करती है। अमीर इतने अमीर हैं कि वे सामाजिक बहुमत से अलग हो जाते हैं। खुली आर्थिक नीतियों ने अमीरों को अपने धन के प्रदर्शित का साहस और स्वाद दिया है। उनकी कार्यप्रणाली उन्हें उन लोगों से अलग करती है जो वेतन पर जीवन यापन करते हैं। वेतनभोगी अपनी आय पर कर का भुगतान करते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह सीधे उनके वेतन से काटा जाता है। लेकिन जो लोग संपत्ति या वाणिज्यिक उद्यमों से आय का आनंद लेते हैं, उनके पास कर से बचने के अनेक उपाय और उपकरण हैं, जिससे उनकी कानूनी पिरामिड में ऊपर तक पहुंच बनी हुई है। सामाजिक पैमाने के निचले स्तर पर, अकुशल या अर्ध-कुशल शारीरिक मजदूरों वाली आबादी का एक तिहाई हिस्सा अनिश्चित भविष्य के साथ श्रमसाध्य दिनचर्या का सामना करता है। असंगठित क्षेत्र में आय से केवल जीविका चलती है, प्रगति नहीं होती।

पारंपरिक राजनीति के प्रति अब किसी का रूझान नहीं है। प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति प्रचलन में है, जिसमें जन प्रतिनिधि स्थानीय लोग नहीं तय करते हैं, बल्कि पार्टी संगठनों के आलाकमान उन्हें चुनते हैं। हालांकि यह कभी कोई नहीं जान पाता कि पार्टी आलाकमान क्या और कौन हैं? यह ढांचा सभी पार्टियों में रहस्य बना रहता है। पूंजी और श्रम के संगठनात्मक ढांचे रूढ़िवादी और अक्षम हैं। यही कारण है कि देश में मेन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में विकास की दर सबसे कम बनी हुई है। देश में धुंधली सामाजिक संरचना बनाने की तेज होती कोशिशें बेचैन करती हैं। हालांकि कोई भी भारत में सामाजिक क्रांति को उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन, कोई भी तेजी से भारतीयकरण की उम्मीद भी नहीं कर रहा है, सिवाय उस सतही मामलों के जो किसी भी आधुनिक औद्योगिक समाज को पसंद आते हैं, विशेष रूप से उपभोक्ता सामग्री भारत की राजनीतिक संभावनाएं ऐसी ही हैं। जिस विकास के दावे आज किए जा रहे हैं, बहुसंख्यक जन उस विकास के मात्र दर्शक बने हुए हैं, भागीदार नहीं। आज भी जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्र अधिकतर मामलों में अवसर तय होते हैं। नेटवर्किंग और सिफ़ारिश जिनके पास होती है वे अवसर पा जाते हैं और असमर्थ, जो केवल अपनी योग्यता पर निर्भर करता है, वह अपने को धकेला हुआ पाता है, क्योंकि बराबरी की दौड़ में कुछ लोग 100 मीटर आगे से दौड़ शुरू करते हैं। सरकारी योजनाएं जो लाभार्थी को सीधे नकद या अन्न देती है वह बस भूख को कम करती हैं, तात्कालिक राहत प्रदान करती हैं। लेकिन ये योजनाएं गरीब को आत्मनिर्भर उद्यमी या कुशल कारीगर या कर्मचारी नहीं बनातीं। गरीबी बंधित हो रही है, समाप्त नहीं। शहरीकरण और पलायन का जाल पीढ़ीगत गरीबी का निर्माण कर रहा है। गरीब इसलिए पीछे नहीं है कि वह मेहनती नहीं है, बल्कि इसलिए है कि शासन व्यवस्था मेहनत को अवसर में बदलने का उपाय करने में असफल हो रही है। शासन आज के भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा देने का दावा कर रहा है। जीडीपी के आंकड़े उत्साह से भरे हैं, शेयर बाज़ार नई ऊंचाइयों छू रहा है, लेकिन इस चमक के नीचे एक कड़वी सच्चाई छिपी है – भारत का गरीब उसी तेजी से आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ पाने में अपने को असमर्थ पा रहा है। कुछ हाथों में सीमित पूंजी के बढने से देश की जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखती है किन्तु दूसरी तरफ प्रत्येकवित जीडीपी हमें दूसरी सच्चाई से भी रूबरू कराती है। सवाल यह नहीं कि विकास क्यों नहीं हो रहा, सवाल यह है कि विकास सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल पा रहा? हमें यह तय करना है कि हम केवल आर्थिक वृद्धि चाहते हैं या समान अवसरों पर आधारित प्रगति, क्योंकि बिना सामाजिक गतिशीलता के कोई भी विकास न टिकाऊ होता है, न न्यायपूर्ण। विकास का मालब है गरीब का गरीब न रहना, अगली पीढ़ी का बेहतर जीवन जी पाना, और मेहनत के दम पर सामाजिक-आर्थिक हैसियत बदल सकना। यह प्रक्रिया जब ठहर जाती है, तो समाज में असंतोष, हताशा और असमानता गहराने लगती है। देश आज इसी मोड़ पर खड़ा है। जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं अति उपभोग और वित्तीय असंतुलन की आशंका भी बढ़ी है, जो सामाजिक अलगाव, मानसिक दबाव और होड़ की जीवनशैली को जन्म ले रही है।

–अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा, (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



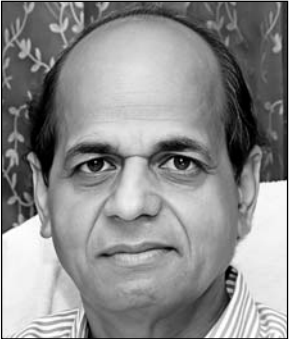
पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

बुधवार 11 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, अनुष्ठान नक्षत्र दिन 1०:53 तक, व्याघ्रात योग रात्रि 2:30 तक, गर करण प्रातः 9:59 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 1०:53 तक है। भद्रा रात्रि 11:11 से आरम्भ होगी।
श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:56 तक, शुभ 11:18 से 12:41 तक, चर 3:26 से 4:49 तक, लाभ 4:49 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 6:12



डॉ. के.लाश चन्द सैनी

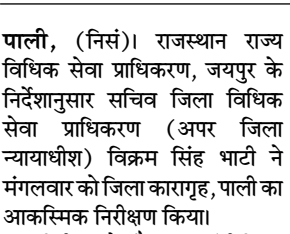
राजस्थान का वर्ष 1952 से 2026 तक का बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज़ नहीं रहा, बल्कि सत्ता, संसदीय परम्परा और परिपक्वता की कहानी भी कहता है। यह 75 वर्षों की उम्र वित्तीय यात्रा का बहीखाता है, जिसने मरू प्रदेश के विकास की दिशा तय की है।

किसी भी विधानसभा के दो प्रमुख काम होते हैं- विधायी और वित्तीय। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विधानसभा ने पिछले 75 वर्षों में न केवल राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी कानूनों का निर्माण किया है, बल्कि प्रतिवर्ष राज्य का बजट पारित कर प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा भी निर्धारित की है। वर्ष 1952 से अब तक की इस यात्रा में जहाँ एक ओर आंकड़ों की विस्तृत दुनिया दिखाई दी है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक नेतृत्व के अनेक रोचक और अर्थपूर्ण रंग भी उभरकर सामने आए हैं। पच्चतर वर्षों के इस संसदीय इतिहास में विधानसभा के सम्मानित सदन में वित्त मंत्रियों द्वारा 74 बार बजट भाषण प्रस्तुत किया जाना इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान ने अपने विकास के हर उतार-चढ़ाव को सजगता और गंभीरता से देखा-परखा है।

शुरुआती सारथी : मिर्धा से



सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी ने जिला कारागृह, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया।



पाली, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी ने मंगलवार को जिला कारागृह, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान 78 बंदी जिला कारागृह, पाली में निरूद्ध मिले। इस दौरान सचिव भाटी द्वारा बंदियों से वार्तालाप कर कारागृह में भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी

व्यास तक

राजस्थान के वित्तीय इतिहास का श्रीगणेश 7 अप्रैल 1952 को हुआ, जब नाथराम मिर्धा ने पहले वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1952-53 का बजट प्रस्तुत किया। राजस्थान की राजनीति के इस कद्दावर नेता का व्यक्तित्व आगे चलकर इतना प्रभावी सिद्ध हुआ कि वे 1979-80 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रहे। अब तक राजस्थान के वित्तीय इतिहास में 20 वित्त मंत्रियों ने राज्य का बजट प्रस्तुत किया है। यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा यह भी रही है कि कई अवसरों पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने स्वयं वित्त विभाग का दायित्व संभालते हुए बजट प्रस्तुत किया। इसी परंपरा की शुरुआत करते हुए जयनारायण व्यास 17 मार्च 1953 को राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी स्वयं निभाई। इसके ठीक बाद, 12 मार्च 1954 को टीकाराम पालीवाल ने वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पालीवाल इससे पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री – दोनों पदों पर रह चुके थे।

सुखाड़िया युग : सत्रह वर्षों का ‘शून्य बजट प्रस्तुति’ काल

राजस्थान के वित्तीय इतिहास का सबसे रोचक और विश्लेषणात्मक तथ्य मोहनलाल सुखाड़िया से जुड़ा है। लगभग 17 वर्षों (1954-1971) तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने स्वयं कभी बजट प्रस्तुत नहीं किया। यह निर्णय सत्ता के विकेंद्रीकरण और मंत्रियों की वित्तीय विशेषज्ञता पर उनके गहरे विश्वास को दर्शाता है। उनके कार्यकाल में वृजसुन्दर शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, बालकृष्ण कौल और मधुरादास माथुर जैसे दिग्गज वित्त मंत्रियों ने सदन में राज्य के आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत किए।

इनमें हरिभाऊ उपाध्याय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1952-56 तक अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद 1957-62 के दौरान राजस्थान का पाँच बार बजट प्रस्तुत किया। यह दौर इस बात का उदाहरण है कि राजस्थान की वित्तीय परंपरा व्यक्ति-केंद्रित न होकर संस्था-केंद्रित रही।

आंकड़ों के जादूगर : गहलोत और राजे
आधुनिक राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का नाम वित्तीय प्रबंधन और बजट प्रस्तुति के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुखाड़िया के बाद सबसे लंबे समय तक राज्य की बागडोर संभालने वाले अशोक गहलोत 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। प्रारंभ में उन्होंने अपने पास किसी भी विभाग का प्रभार नहीं रखा और बजट की जिम्मेदारी विश्वस्त वित्त मंत्री प्रद्युम सिंह को सौंपी, जिन्होंने चार बार बजट प्रस्तुत किया। प्रद्युम सिंह ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्हें विधानसभा के टाउन हॉल स्थित पुराने भवन और ज्योतिराम स्थित नए भवन– दोनों में बजट पेश करने का अवसर मिला। तेरहवीं और पंद्रहवीं विधानसभा के कार्यकाल में अशोक गहलोत ने अपने सभी 10 बजट स्वयं प्रस्तुत किए।

इसी प्रकार, वसुंधरा राजे ने बारहवीं और चौदहवीं विधानसभा के अपने दोनों कार्यकालों में सभी 10 बजट स्वयं पेश कर सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसकी बराबरी आगे चलकर अशोक गहलोत ने की। तीन बार प्रदेश की बागडोर संभालने वाले भैरोंसिंह शेखावत अपने दूसरे और तीसरे कार्यकाल में कुल 6 बार बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री रहे। उनके पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री मास्टर

इतिहास सदैव एकरेखीय नहीं होता। एक अवसर ऐसा भी आया जब राष्ट्रपति शासन के कारण राजस्थान विधानसभा के स्थान पर राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति ने वर्ष 1993-94 का बजट लोकसभा में पेश किया। वित्तीय विषयों में सिद्धहस्त और अनुभवी मानिकचन्द सुराणा की यह विडंबना रही कि वित्त मंत्री होने के

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से

अजमेर, (निसं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार 12 फरवरी से राज्यभर में प्रारंभ होंगी। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में 19 लाख 90 हजार 57 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश में 6194 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष सैकेंडरी परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 109, सीनियर सैकेंडरी परीक्षा में 9 लाख 10 हजार 9, प्रवेशिका में 7 हजार 817 तथा वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4 हजार 122 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा

अज्ञात जंगली जानवर ने कई मवेशियों को मारा

सादुलपुर, (निसं)। गांव ग्वालीसर में सोमवार व मंगलवार की रात्रि को अज्ञात जंगली जानवरों के हमले में अनेक मवेशियों की मौत व घायल होने का मामला सामने आया है तथा अनेक मवेशी गायब बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पशुपालक नवीन अपने 85 मवेशियों को रिवाड़े में बन्द कर पास ही बने मकान में सो गया। हमेशा की तरह सुबह 7-8 बजे मवेशियों को संभाला तो दंग रह गया। इसी दौरान रिवाड़े में अनेक भेड़ लहलुहान पड़ी थी, जिसमें

कई मवेशियों की मौत हो चुकी थी तो कई मवेशी घायल थे। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग जल्द से जल्द अज्ञात जंगली जानवर का रेस्क्यू करें ताकि ग्रामीणजन व पशुपालकों को राहत मिल सके। पशुपालक नवीन ने बताया कि वह मवेशियों का पालकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर जीवन यापन करता है, मगर अन्न उसके सामने रोजी-रोटी का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि 35 मवेशी गायब हैं, तथा गांव में अज्ञात जानवर बताया जा रहा है।

सिंह डिग्गी, भाजपा नेता हिम्मतसिंह झाला, राजस्थान विद्यापीठ के वाइस चान्सेलर कलत पुर. एस.एस. सारंगदेवोत, भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक रणधीरसिंह भीण्डर, वीरन्द्र रावणा, वीरमदेवसिंह कृष्णावत, यदुराजसिंह कृष्णावत को क्षत्रिय शिरोमणी विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया।

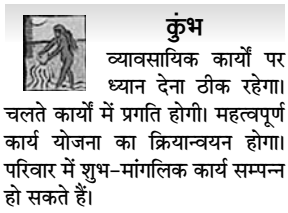


कन्या

परिवार में मन को प्रसन करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।



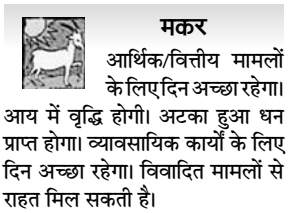
मीन



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।

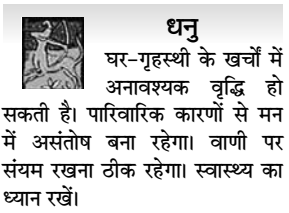
चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना के क्रियान्वयन होगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



मकर

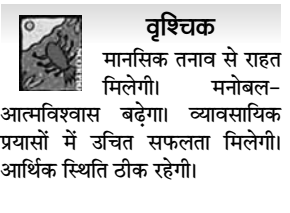
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिएदिन अच्छा रहेगा।

आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।



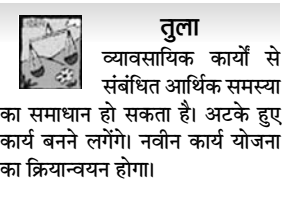
धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों से मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



वृश्चिक

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उत्थित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

